

## President Roosevelt and the New Deal

4 मार्च, 1933 ई० को जॉर्ज रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया तो अर्थव्यवस्था की स्थिति अत्यंत गंभीर एवं बेचीदा हो चुकी थी। रूजवेल्ट ने रात्रारुह होते ही सर्वप्रथम कार्य देश को आर्थिक संकट से मुक्त कराने के लिए उठाया किया। उसने आपने उद्देश्यों को इस प्रकार से व्यक्त किया: "हमारा कार्य उन्नी उन साधनों और संस्थाओं का निर्माण करना है जो हमारे पास हैं। अनिश्चित उत्पादन के लिए विदेशी बाजार प्राप्त करना और उपभोग, आर्य-उपभोग, धन और उत्पादन के समान वितरण को समझाएँ वाद की चीजें हैं।" 6 मार्च 1933 ई० को ही एक आपातकालीन घोषणा में उसने राष्ट्र भर में बैंक सुगमन रूग्मन की घोषणा की तथा स्वर्ण के उगम-जाने पर रोक लगा दी। उसी दिन ही स्वर्ण मान को समाप्त कर दिया। इस संबंध में दो विद्योक्तों को पारित किया गया जिन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है - प्रथम, आकालीन और आवश्यक समाधुओं से संबंधित तथा द्वितीय, स्थायी उद्योगों से संबंधित। वे दोनों प्रकार के विद्योक्तों को प्रमत्ता, सहायता एवं पुनरुत्थाव तथा सुचारु और पुनर्निर्माण की संज्ञा दी गयी तथा उन्हें सामूहिक रूप से नया कार्यक्रम या New Deal का नाम दिया गया जिसका मुख्य उद्देश्य एक आर्थिक विकास कार्यक्रम का निर्माण करना था।

रुजवैल्ट की न्यू डील नीति को चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है :-

(A) प्रथम वर्ग की नीतियाँ :-

उद्योगिक नीति :- उद्योगिक संकट ने उद्योग संरक्षण उद्योगिक उपकरण उपलब्ध कर दिया था। रुजवैल्ट का मह विचार था कि उद्योगिक मंत्री इस कारण ही दुर्ग हैं कि उद्योगपतियों की पर्याप्त लाभ नहीं हो रहा है, वे हानि उठा रहे हैं। लाभ इसलिए नहीं हो रहा है कि वस्तुओं का मूल्य बहुत ही घट गया है और वस्तुओं का मूल्य इसलिए घट गया है कि उद्योग ही अधिक प्रतिभोगिता हो गयी है। अतः इसका उपाय यह हुआ कि प्रत्युत्थान के लिए लाभ में प्रति उद्योगिक है जिसके लिए प्रतिभोगिता में कमी करना आवश्यक है। सरकार ने उद्योग निवेश करने की योजना की और निवेश के लिए उत्प्रेरणा देने के लिए व्यवस्था की। रुजवैल्ट ने इस क्षेत्र में पाँच उपाय किया :-

(1) राष्ट्रपति को विद्यायिका द्वारा 33,000 डॉलर लोक काम पर व्यय करने के लिए प्राधिकृत किया गया। लोक काम पर व्यय द्वारा उद्योग वोजगार और फलदा वस्तुओं के लिए उद्योग माँग की सृष्टि करी जा सकती थी।

(2) सरकार ने प्रत्येक उद्योगपति को एक औद्योगिक संहिता बनाने के लिए अनुदेश दिया जो उद्योग एवं उचित प्रतिभोगिता की व्यवस्था कर वस्तुओं के मूल्यों को उंचा रख सकती थी।

(3) आर्थिक संघों द्वारा सामूहिक मूल्य नीति की व्यवस्था करने के लिए विद्यायिका ने कुछ विधियाँ निर्मित की।

रुजर्वेल्ट का मत था कि प्रत्युत्थान के लिए यह आवश्यक है कि जनता न्यायिक से आर्थिक वस्तुओं का प्रभु बनने लगे। यह तभी संभव है जब जनता की न्याय न्यायिक हो। इसके लिए वेतन, मजदूरी की आर्थिक होनी चाहिए।

(4) राष्ट्रपति की न्यूनतम मजदूरी, कार्य करने के लिए अन्यायपूर्ण धंडे एवं सेवा की अन्याय शर्तों को निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया गया।

(5) उस समय कुछ काल के लिए डेमा ग्रेटिंग दल की परम्परागत प्रथास विरोधी नीति का पता कर दिया गया था। राष्ट्रीय उद्योगिक प्रत्युत्थान आधिनियम सन् 1933 से 1935 तक लागू होता रहा किन्तु सन् 1935 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अतः यह समाप्त हो गया।

(B) द्वितीय वर्ग के उपाय :-

कृषि नीति :- सन् 1929 ई० की ही कृषि प्रत्युत्थान के लिए प्रयास किए जा रहे थे। राष्ट्रपति रुजर्वेल्ट ने फसल प्रतिबन्ध की नीति अपनायी। यह एक पूरक आधिनियम सन् 1933 ई० में निर्मित किया गया। जिसे कृषि सामाजिक आधिनियम कहा गया है।

प्रश्नः